

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 28, गुरुवार, शाके 1944-अक्टूबर 20, 2022 Asvina 28, Thursday, Saka 1944- October 20, 2022	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(पी.पी.पी. डिवीजन)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2022

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

2013 धारा 4(1)

संख्या प.7(656) एस.एच.ए/पी.पी.पी/2021-22/ :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार एन.एच. 12 से लक्ष्मीपुरा-डोरा-डाबी-राणाजी का गुढा एस.एच. 115 को डी.बी.ओ.टी. हाईब्रिड एन्यूटी माध्यम से 2 लेन/इन्टरमीडिएट लेन में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बूंदी में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	बून्दी	तालेड़ा	लक्ष्मीपुरा
			छांट का खेड़ा

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा “मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली” एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत /नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

1. श्री राकेश कुमार सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ),

2. श्री अरविंद कुमार सिंह (पुनर्वास विशेषज्ञ),

कार्यालय- मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली

वास्ते श्री यशवन्त सिंह तोमर

मकान सं. बी-12, नन्दपुरी, संकटमोचन हनुमान मंदिर के पास,

गली नं.-7, हवासड़क, बाईस गोदाम, जिला-जयपुर,

(राजस्थान) - 302019.

मोबाइल नं.- 9079398209

ई-मेल:office.masmjaipur@gmail.com

आदेश द्वारा

सुनील गुप्ता,

संयुक्त सचिव, (पथ)

सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।